दैनिक भास्कर
dainikbhaskar.com

मेट्रो के लिए हाइवे पर रूट का सर्वे शुरू

भास्कर न्यूज & फरीदाबाद

मेट्रो के रूट को लेकर डीएमआरसी ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले मेट्रो के रूट के लिए डीएमआरसी द्वारा सेटेलाइट सर्वे कराया गया था। इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब मेट्रो रूट के लिए मैदानी सर्वे शुरू हो गया है। मेट्रो की अलाइमेंट को लेकर इंजीनियर सर्वे करने में जुट गए हैं। इस सर्वे में यह देखा जा रहा है कि सराय से लेकर वाइएमसीए तक कितने निर्माण, पेड़, सीवरेज व बिजली के खंभे आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह पता लगेगा कि रूट के रास्ते में कितने निर्माण व बाधाएं आ रही हैं। इसके बाद ही इस रूट पर कोई काम शुरू होगा। फरीदाबाद में मेट्रो की सुगबुगाहट से ही यहां डीएमआरसी ने सेटेलाइट सर्वे कराया था। इस सर्वे में देखा गया था कि मेट्रो के रूट के तहत कौन-कौन से निर्माण आ रहे हैं। इसके बाद जब इस प्रोजेक्ट के बजट को प्रदेश सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है तो अब इसका मैदानी सर्वे भी शुरू हो गया है। इस सर्वे के लिए डीएमआरसी ने मैपैज इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी को ठेका दिया है। इस सर्वे की रिपोर्ट डीएमआरसी को सौपने के बाद यहां पिलर खड़े करने का काम शुरू करा दिया जाएगा।

मिट्टी निरीक्षण के कार्य ने पकड़ी गति

मेट्रो के पिलर गाडऩे के लिए चल रहे मिट्टी के निरीक्षण कार्य ने भी गति पकड़ ली है। अभी तक १३ से अधिक स्थानों पर सैंपल लिए जा चुके हैं। पहले यह काम दो जगह चल रहा था लेकिन अब चार जगह मशीने लगा दी हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ९० सैंपल लेने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। मेट्रो प्रथम चरण में बदरपुर बॉर्डर से लेकर वाईएमसीए तक आएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने योजना के लिए 1589 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इस योजना पर करीब 2233 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कुछ भाग केंद्र सरकार देगी। अभी केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाले राशि को स्वीकृति नहीं दी है। मेट्रो का निर्माण कार्य 2011 में शुरू व 2013 में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। बॉर्डर से लेकर वाईएमसीए के बीच मेट्रो के कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। हुडा प्रशासक डी सुरेश का कहना है कि साइट चयन के बारे में डीएमआरसी अधिकारी तय करेंगे। उन्होंने दोनों सेक्टर का प्रपोजल बनाकर भेज दिया है। मेट्रो के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर दलजीत सिंह के अनुसार इस योजना के लिए डिपो के चयन की प्रक्रिया पेंडिंग है। इसके अलावा सेंटर गवर्नमेंट से भी बजट को हरी झंडी नहीं दिखाई गई है।